"That the damnd under the head Railway Board be reduced by Rs. 100."

[Need to take steps to avoid congestion on railway platforms and improve the sanitary conditions on all Delhi Railway stations (331)]

"That the demand under the head Railway Board be reduced by Rs. 100."

[Ignoring of Scheduled Tribes in the recruitment in the Railway Department, particularly in the scale of officers (332)]

"That the demand under the head Construction of new Lines—Capital and Depreciation Reserve fund be reduced by Rs. 100."

[Failure to construct railway line from Sampla, District Rohtak to Jhajjar Tehsil of the same district and connect Jhajjar Tehsil to Bahadurgarh to Rohtak district (Haryana) (333)]

MR. DEPUTY-SPEAKER: The cut motions are also before the House.

15.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

FOURTEENTH REPORT

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur): I beg to move:

"That this House do agree with the Fourteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 15th March, 1978."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Fourteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 15th March, 1978."

The motion was adopted.

15.31 hrs.

RESOLUTION RE: REPEAL OF CONSTITUTION (FORTY-SECOND AMENDMENT) ACT AND WITHDRAWAL OF MISA—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall now take up further discussion of Shri Samar Guha's following Resolution for the repeal of Constitution (Forty-second Amendment) Act and withdrawal of MISA:

"This House recommends to the Government to redeem its sacred pledge, made to the people on the historic occasion of the last Lok Sabha Election, by forthwith repealing the Constitution (Forty-second Amendment) Act, which was passed by Parliament under a precarious condition of *de facto* captivity during the repressive Rule of Emergency and which aimed at conspiratorially crippling the democratic freedom of the Indian people and subverting the basic principle of Rule of Law in an unholy effort to perpetuate a quasi-authoritarian administration in the country in abject violation of the fundamental objective of the Indian Constitution, and recommends further to withdraw immediately the Maintenance of Internal Security Act (MISA) which was atrociously used during the above days of darkest period of our democracy as the main arm of suppression and oppression of the people in an ugly desire to protect the personal dictatorship of the former Prime Minister in utter defiance of the sovereign will of the people."

Shri Vinayak Pradsad Yadav may continue his Speech.

श्री हरि विष्णु कामंत (होशंगाबाद) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मेरे पास श्री समर गुहा का एक तार आ गया है, हो सकता है आपके पास भी आया हो ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have not yet reached that stage of discussion.

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय जनता पार्टी की सरकार बने हुए लगभग एक साल हो रहा है । श्री समर गुह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, जिस पर हम चर्चा कर रहे है, मैं समझता हूं इस प्रस्ताव को रखकर उन्होंने इस देश का और जनता पार्टी का बहुत बड़ा उपकार किया है । उन्होंने इस बात को याद दिलाया है कि 1977 के आम चुनाव के समय हमने जो प्रतिज्ञा की थी इस देश की जनता से उसको हमें पूरा करना चाहिए । अब वह समय आ गया है जब इसको एक दिन के लिए भी मुल्तवी नहीं किया जा सकता है ।

आप देखें कि क्या स्थिति है ? आप देश के किसी भी कोने में चले जायें, उत्तर प्रदेश, बिहार या दक्षिण के किसी प्रदेश में चले जायें, जहां भी आप जायेंगे आप देखेंगे कि किसी न किसी तरह का आन्दोलन शुरू हो गया है । हर जगह छात्र संगठन, युवा जनता के लोग सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आपने वायदा किया था मंहगाई घटाने के लिए, आपने वायदा किया था बेकार लोगों को काम देने के लिए, एक साल हो गया है और हम अभी तक बेरोजगार हैं, अब हम एक दिन भी नहीं रुक सकते हैं, आप अपने वायदों को पूरा करें ।

जब हमारा संविधान है उसके आर्टिकल 16(4) में लिखा हुआ है कि सरकारी सेवाओं में आबादी के जिस अंश का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा उसके लिए सरकार अविलम्ब स्टेट कानून बना करके उचित प्रतिनिधित्व देगी । 1977 के आम चुनाव के पहले जब जनता पार्टी का मेनिफेस्टो बन रहा था तो उसमें हमने कहा था कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जिनका सरकारी सेवाओं में नगण्य स्थान है उसके लिए, जिन मुठ्ठी भर लोगों ने सरकारी सेवाओं को मोनोपोलाइज कर लिया है उनकी मानोपोली को खत्म करके, जिनका उचित रिप्रेजन्टेशन नहीं है उनको उचित रेप्रेजेन्टेशन देने के लिए कानून बनायेंगे । लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने उसको पूरा नहीं किया है । बिहार में इस मामले को लेकर आग लगी हुई है । जो लोग सदियों से उपेक्षित हैं उन्होंने अंगड़ाई लेनी शुरू की है । इसीलिए मैं ने कहा कि श्री समर गुह ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है वह बहुत ही मौजं है । समूचे सदन को एकमत से उसे पारित करके सरकार से कह देना चाहिए कि जितने भी वायदे किए गए हैं, चाहे मीसा सम्बन्धी वायदा हो या अनएम्पलायमेंट सम्बन्धी हो वह पूरा किया जाये । चाहे पिछड़े वर्ग को संरक्षण का वायदा हो, चाहे महंगाई खत्म करने का वायदा हो, सबको एक-एक कर के हम को पूरा करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज परिस्थिति देश में बदल गई है । 30 साल तक देश में कांग्रेस की हकूमत थी । हर पांच साल के बाद कांग्रेस के लोग चुनाव के समय मैनिफैस्टो ले कर आते थे और चुनाव के बाद उस मैनिफैस्टो को भूल जाते थे । जनता भी सोई रहती थी, कोई अन्दोलन वगैरह नहीं होता था । लेकिन अब देश की परिस्थिति इतनी ज्यादा बदल गई है कि एक साल तक वायदा-खिलाफी देखने के बाद समूचे तबके के लोग अपनी-अपनी मांगों को लेकर उठ खड़े हुए हैं । यदि हम ने अपने उन वायदों को जो हम ने 1977 के चुनाव के पहले जनता से किये थे—यदि इन चुनावों के बाद देश में कांग्रेस की हुकूमत खत्म हो गई और हमारी सरकार बनी, तो हम फला-फला काम करेंगे—उन वायदों को यदि हम ने पूरा नहीं किया तो देश में एक वावैला मच जाएगा ।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये इस सोवरेन-पार्लियामेन्ट के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव इस समय हमारे सामने है, उस को हमे सर्व-सम्मति से पास करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज क्या स्थिति है ? हमे यह देख कर आश्चर्य होता है—एक तरफ तो हम सरकार पर यह दबाव डाल रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन को आउट-राइट रिजेक्ट करना चाहिये, मीसा को खत्म करना चाहिये, ये कानून जिस समय हुकूमत हमारे हाथ मे आई थी, उसी समय हो जाना चाहिये था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दूसरी तरफ सरकार उसी मीसा को दूसरी शक्ल में लाना चाहती है । हम लोगो को मालूम है—मैं अपनी ही बात आप के सामने कहना चाहता हूं—जब इन्दिरा गांधी ने कोर्ट के दरवाजे बन्द कर दिये थे, मीसा लागू कर दिया था, समूचे देश को एक तरह से जेल-खाना बना दिया था, हम लोगो को मीसा मे बन्द कर दिया गया था, हम लोगो के घरो को कुडक किया गया, सब सामान जब्त किया गया, माल-मवेशी ले गये। हम लोगो का ही नही, मान लीजिये हमारे खिलाफ मीसा का वारट निकला था और हम मौजूद नही थे, तो गाव मे हमारे बगल मे जो लोग रहते थे, उन के माल-मवेशियो को उठा कर ले गये उन की सारी जायदाद को जब्त कर लिया गया और कोर्ट मे इस के खिलाफ कोई सुनवाई नही होती थी । इतने बडे जुल्म के बाद जब हम लोग बाहर आये, तो हम ने जनता से कहा था—यदि जनता पार्टी की हुकूमत आयेगी तो देश के अन्दर रूल-आफ-ला इस्टेब्लिश किया जायेगा, कानून का राज्य कायम किया जायेगा—जनता से यह हमारा वायदा था। दूसरा वायदा हम ने यह किया था कि जो क्रिमनल प्रोसीजर कोड है, उस में भी हम संशोधन करेंगे, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, क्या संशोधन हो रहा है ? शायद आप ने भी देखा होगा एक तरह से संशोधित रूप मे मीसा को हम क्रिमनल प्रोसीजर कोड म प्रस्थापित करने जा रहे हैं । वह मीसा जो एमर्जेन्सी का मीसा था, उस से भी ज्यादा भयानक रूप मे यह दूसरा मीसा आ रहा हैं । इस लिये मैं आप के जरिये सदन के माननीय सदस्यो से कहना चाहता हू कि यह जो प्रस्ताव सदन के सामने है, इस को हमे पारित करना चाहिये और यदि हम ने ऐसा नही किया, तो आप समझ लीजिये कि अब 30 साल पहले की जनता नही है, 30 साल पहले के हिन्दुस्तान का छात्र नही है, यदि वे देखते है कि हम वायदा खिलाफी कर रहे हैं तो वे अगडाई लेना शुरु कर देते हैं। इसलिये हम-भूल-भूलैया मे न रहे । कांग्रेस ने तो तीस साल तक अपने वायदो को पूरा न कर के हुकूमत कर ली, लेकिन हम यदि अपने वायदे को भुला कर, कार्यान्वित न कर के, 10-15 साल भी इस देश मे हुकूमत करना चाहे, यदि यह बात हमारे दिमाग मे हो, तो मै समझता हू कि इस मे बडी भूल कोई नही होगी । हम को जनता एक मिनट भी बरदाश्त नही करेगी यदि जितने वायदे हम ने जनता से किये हैं, उन को पाच साल के अन्दर पूरा कर के नही दिखलाया ।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, हम समर गुह साहब को धन्यवाद करते है और हम समझते है कि चाहे मीसा के बारे मे, चाहे सम्पत्ति के बारे मे, चाहे फण्डामेन्टल राइट्स के बारे मे या जो भी वायदे हम ने जनता से किया है, उन को हमे पूरा करना चाहिये । जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद एक ही क्रेडिट उस को मिल सकता है और वह यह कि हम ने इमर्जेन्सी को खत्म किया और इस देश मे डेमोक्रेसी को पुनस्थापित किया । यही हमारा एकमात्र क्रेडिट है इस एक साल मे लेकिन हम जो क्रिमिनल कोड मे एमेडमेंट करने जा रहे है, उस से हम अपने उस क्रेडिट को खत्म कर देंगे । इसलिये मै माननीय सदस्यो से

[श्री विनायक प्रसाद यादव]

निवेदन करता हूं कि जो हरकत सरकार करना चाहती है डेमोक्रेसी को करटेल करने के लिए, नागरिको की आजादी पर कुठाराघात करने के लिए और कोर्ट का दरवाजा बन्द करने के लिए, उस को हम लोगों को नही चलने देना चाहिए और इस तरह की कार्यवाही सरकार को नही करनी चाहिए ।

आप के जरिये मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश मे छात्र आन्दोलन का जहा तक सवाल है, इस छात्र आन्दोलन पर इसी हाऊस मे काल एटेंशन आया है और यही नही कि उत्तर प्रदेश मे ही विश्वविद्यालय बन्द है बल्कि बिहार मे भी चार, पाच जो यूनिवर्सिटिया है, उन को होली की छुट्टी के पहले ही बन्द कर दिया गया । होली की जो छुट्टिया होती थी उस के पहले ही समूचे बिहार की यूनिवर्सिटियो को बन्द कर दिया गया है क्योंकि सरकार को यह डर हो रहा है कि अगर सभी यूनिवर्सिटियो को बन्द नही किया गया, तो अनएम्पलायमेंट के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अमन-चैन देश मे बिगड रहा है, वह और न बिगडे । यह जो आन्दोलन हो रहा है, उस को यूनिवर्सिटियो को बन्द कर के क्या रोका जा सकता है और कितने दिन यूनिवर्सिटियो को बन्द कर के आप उस को रोक सकते हैं । जनता के साथ जो वायदे किये गये हैं उन को पूरा किये बगैर आप इस को नही रोक सकते है । जनता पार्टी और जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर जब जनता को दिये गये वायदो को पूरा करेगी, तभी जा कर आन्दोलन खत्म हो सकता है और देश में अमन चैन हो सकता है और देश को आगे बढ़ाने का भी काम हो सकता है । इसलिए मैं आप के जरिये फिर माननीय सदस्यो से कहना चाहता हूं कि वे इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करें और आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया है, उस के लिए आप को धन्यवाद देता हूं ।

MR DEPUTY SPEAKER: The position is that we have exhausted the time that was allotted for this resolution.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I have received a telegram from my esteemed friend and colleague, Shri Samar Guha. It reads as follows: "Unwell—from Calcutta it has come—

"kindly defer my right of reply next day"' Now, Sir, we may take that into consideration. I am given to understand that the hon. Minister also wishes to intervene.

SHRI CHITTA BASU (Barasat): We shall also. .

MR DEPUTY-SPEAKER: There is no question of "we shall also". If at all, we can only think of his right of rely. Mr Chitta Basu, you please understand the position

SHRI CHITTA BASU: What is the position?

MR DEPUTY-SPEAKER: The position is that the time allotted for this resolution is exhausted. I must make one remark here because I have been waiting for a long time to make it You see, there are several people who give notice of the resolutions One Member gets at No 1, the other Member gets at No 2 and it is so happening in this House that everytime somebody gets No 1, he keeps on extending the time and then the No 2 has absolutely no meaning I think that position should stop and the Members should also understand it.

Yes, Mr Kamath, you may continue.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I am given to understand that the Minister would like to intervene when the mover of the resolution, Mr Guha, is present in the House. So, under Rule 340, I move that the debate on this motion be adjourned. Rule 340 may be read with proviso to Rule 29, which reads as follows:

"Provided that notwithstanding anything contained in Rules 27 and 28, any such business which is under discussion at the end of that

day—that is, today—shall be set down for the next day allotted to business of that clause—that is, a fortnight hence—and shall have precedence over all other business set down for that day."

So, Sir, if the Rules permit, I would like to move that the debate on the resolution be adjourned to the next day set down for this business, i.e., 31st March.

MR. DEPUTY-SPEAKER: But, Mr. Kamath, you cannot read the two rules together.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Why not?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can move for adjournment, but then it will mean that it has to get again into the ballot.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: These two rules, are they incompatible? How can they be incompatible?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, they are absolutely different as far as I can see.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: But, Sir, a Member should get the benefit of the rules.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Sir, Before Mr Kamath can move for adjournment, there will be further difficulty as I see from your point and that is, if the time is exhausted, as you say, for this particular Resolution by Shri Samar Guha, and as I see your point that the other resolution has also come up by priority, then befoe Shri Kamath's move for adjournment is acceptable to you and to the House, at least you must agree to extend the time allotted for this resolution. Otherwise, without agreeing first for the extention of time allotted for this resolution, what are you adjourning? The House must first agree to the extension of time. If the House does not agree to the extension of time, then Mr. Kamath's move for adjournment of the debate has no meaning, because adjourning for what if the time is exhausted? That is my point. So, I think the House must first agree if it wants that the time allotted for Shri Samar Guha's resolution be extended by one hour. If that is agreeable to the House, then Shri Kamath's motion for adjournment can be put. That is my contention.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: How much time was allotted for this?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Two hours. There are still five minutes more.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Was it not extended last time by one hour?

MR DEPUTY-SPEAKER: I do not know . No, it was not extended.

PROF. P. G MAVALANKAR: That is why I am suggesting. Sir, let us extend the time for debate by one hour and then Mr. Kamath may move the motion and then we can proceed to the next resolution.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is up to the House But if it is for adjournment, Rule 30 will also apply which means that it shall not be set down for further discussion unless it has gained priority at the ballet That is there in the Rule.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Any way five minutes still remain for the next day. It can be extended next day.

MR DEPUTY-SPEAKER: Provided it gets in the ballot. Any way, you can move.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: What about Rule 29, Sir?

MR DEPUTY-SPEAKER: You can move for adjournment of the debate.

[Mr. Deputy Speaker]

Five minutes is there and when we take it up, then you can ask for extension of time.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Is proviso to Rule 29 not applicable?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, but Rule 30 follows. Rule 30 speaks about adjournment.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: They are contiguous, in juxtaposition- check by jow!

MR DEPUTY-SPEAKER: That is why I said the difficulty is that it has to get into the ballot Any way you can move for adjournment.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I move that the debate on the Resolution be adjourned under Rule 340 to the next day set down for this business, i e, 31st

MR DEPUTY-SPEAKER Is it the pleasure of the House that the debate on the Resolution be adjourned?

SOME HON MEMBERS Yes

MR DEPUTY-SPEAKER: The debate is adjourned

15.49 hrs

RESOLUTION RE: CONTINUANCE OF ENGLISH AS ADDITIONAL LINK LANGUAGE

SHRI S D SOMASUNDARAM (Thanjavur): Sir, I beg to move:

> "This House do urge upon the Government to amend the Constitution so as to implement Pandit Nehru's solemn assurance to Parliament that, besides Hindi being the link language, English would continue as additional link language so long as non-Hindi speaking people want it."

This assurance was given by the late Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. But from that time in the House as well as outside, non-Hindi-speaking people have been demanding for the Constitutional amendment. I would ask the Home Minister why the assurance was given, when it was given, to whom it was given and under what circumstances it was given. The Prime Minister of the country will not be giving an assurance to anybody at anytime. An assurance is given when there is such a need because of the political atmosphere in the country. Under certain particular circumstances, Pandit Jawaharlal Nehru gave that assurance We demand that assurance must be given constitutional protection.

It is claimed that Hindi should become the link language of the States. because it is spoken by 42 per cent of the population If this 42 per cent were to be scattered throughout the length and breadth of the country, from Cape Comorin to Himalayas, the argument would be logical But this 42 per cent is concentrated in one compact area, that is, the States of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. Therefore, if this 42 per cent is taken into consideration, it would be a permanent advantage to the people of this area and a parmanent disadvantage to the people living in other areas. If, instead of 42 per cent, even if it is only 20 to 30 per cent, if Hindi is spoken throughout India, say, by 50 lakhs in Tamil Nadu, 30 lakhs in Kerala, 30 lakhs in Karnataka, 75 lakhs in Andhra and 80 lakhs in West Bengal and Assam and soon, then only we can say that Hindi is spoken throughout India

If the Hindi-speaking people are scattered throughout India, it may be the logical thing that Hindi may be the official language of the States. It can also be the link language.